अगली पीढ़ी की बैंकिंग की चुनौतियां*

के.सी. चक्रवर्ती

श्री कृष्णन, अध्यक्ष, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोयंबतुर; श्री एम.नरेंद्र, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडियन ओवरसीज बैंक; श्री डी.राज कुमार, क्षेत्रीय महा प्रबंधक, द हिंदू; श्री के.जी.बालकृष्णन, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईसीसीआई) कोयंबतुर; आईसीसीआई के सदस्य और कोयंबतुर के उद्योगों के प्रमुख; कोयंबतुर के बैंकों के प्रतिनिधि; प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मिडिया के सदस्य; अन्य सम्माननीय आमंत्रितगण, देवियो और सज्जनो।

1. मुझे यहां "वॉइस ऑफ टुमारो - फ्यूल टू एक्सेल" कार्यक्रम, जो कि आईसीसीआई, कोयंबतुर और द हिंदू की प्रशंसनीय पहल है, में भाषण देते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

2. शुरू में ही यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब हम कल की आवाज की बात कर रहे हैं तब हम किसकी आवाज के संबंध में बात कर रहे हैं। मेरे अनुसार कल की आवाज देश के युवाओं और लाखों कारोबारी उद्यमियों की होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि कारोबारियों की आवाज आज नहीं सुनी जाती। किंतु आईसीसीआई जैसे संगठनों के माध्यम से उनके संगठित होने की एक सीमा है। मेरा आशय देश भर के लाखों निजी उद्यमियों की सामूहिक आवाज से है। युवाओं की आवाज के साथ यह वह आवाज है जो देश के भविष्य को तय करेगी और उसे बनाएगी।

3. भविष्य में इस देश के युवाओं की आवाज बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाएगी। और बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था में जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में और भी सुधार होने हैं, अर्थव्यवस्था को स्वरूप देने में निजी कारोबारी समुदाय का योगदान बढ़ता जाएगा और भविष्य में हमारी सोच को रूप देने में उनकी आवाज का महत्त्व बहुत बढ़ जाएगा। इस संदर्भ में कोयंबतुर जैसे औद्योगिक शहर का महत्त्व बढ़ जाता है।

4. श्री नरेंद्र ने उल्लेख किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि तथा 12 वीं योजना में 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। मेरा मानना है कि भारत में अगले 20 वर्ष तक 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है और तभी यह वृद्धि वास्तव में दीर्घकालिक और समावेशक होगी। निजी उद्यम और निवेश के साथ ही जनसांख्यिकीय लाभ भविष्य में देश में व्यापक वृद्धि की संभावना के मूल प्रेरक बन सकते हैं। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि पिछले दशक का भारत का नया वृद्धि पथ निजी निवेश में तेज वृद्धि और युवा जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ हुआ है। अत; इन दोनों कारकों के कारण हम विश्वास कर सकते हैं कि भविष्य में 10 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करके उसे बरकरार रखा जा सकता है।

5. इस दर पर, वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 2030 तक वर्तमान के 2 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन यह स्वत: नहीं होगा। मात्र नीति तैयार करने से वृद्धि नहीं होगी। यह तभी हो सकता है जब हम चुनौतियों पर सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ा श्रम करें और वैश्विक तथा देशी गतिविधियों से प्राप्त हुए अवसरों का लाभ लें। अब मैं प्रमुख चुनौतियों और अवसरों की चर्चा करना चाहूंगा।

6. श्री नरेंद्र ने जनसांख्यिकीय लाभ की बात की है। दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अगले 20 वर्षों तक कार्यक्षम जनसंख्या बढ़ेगी। युवा जनसंख्या हमें अवसर प्रदान करती है किंतु पर्याप्त उत्पादक रोजगार के अवसर निर्मित करने की चुनौती पर सफलता हासिल करने पर ही यह निर्भर होगा कि हम कितना जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2014 तक कार्यक्षम आयु की जनसंख्या की भारत में 312 मिलियन वृद्धि होगी जबकि चीन में यह 126 मिलियन कम हो जाएगी। इन युवाओं के लिए श्रम बाजार में लाभदायक रोजगार उत्पन्न करना बड़ी चुनौती है किंतु यह असंभव नहीं है।

7. यहां शिक्षा और कौशल विकास की चुनौती है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए व्यापक गुंजाइश बनायेगा किंतु जनसांख्यिकीय लाभ तभी मिल पायेगा जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वहनीय बना पायेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष की सहायता से गुणवत्तापूर्ण

* डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25 जून 2011 को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोयंबतुर में दिया गया भाषण।

शिक्षा की इकाई लागत कम करके ऐसी शिक्षा को पहुंच में और वहनीय बनाया जा सकता है। यह वह स्थिति है जहां कोयंबतुर, जो कि शिक्षा और उद्यमशीलता की कुशलता का केंद्र है, पुरोधा की भूमिका निभा सकता है।

8. हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का समग्र कौशल आधार कम है। इस पर विश्वास करना कठिन है क्योंकि हमारे आईटी व्यावसायिकों को वैश्विक तौर पर मान्यता मिली है और ज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान सर्वविदित है। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि सिलिकॉन वैली में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाले हमारे युवा अपने स्वयं के देश में ऐसा करने में क्यों विफल होते हैं।

9. देश की जीडीपी में 65 प्रतिशत हस्सा सेवाओं का होने के कारण कोई भी यह सोच सकता है कि भारत की वृद्धि कौशल-प्रधान होनी चाहिए। किंतु तथ्यों के अनुसार स्थिति इसके विपरीत है। अनेक विकसित देशों में 15-29 के आयु समूह के 60-80 प्रतिशत लोग टर्सियरी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और कोरिया में तो यह स्तर 96 प्रतिशत है। भारत में यह स्तर 15 प्रतिशत से भी कम है। अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर विकसित देशों में जीडीपी का 2 से 3 प्रतिशत व्यय किया जाता है जबकि भारत में यह मात्र 0.8 प्रतिशत है। इससे ही हमारे देश में नियोजन और नियोजनीयता के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस अंतर को किस तरह से पाटा जाए यह भविष्य की योजना बनाने वालों के सामने चुनौती है।

10. कौशल की कमी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महंगी होती जाएगी। 1948 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में भाषण देते समय मौलाना आजाद ने कहा था कि "हमें यह बात एक क्षण के लिए भी नहीं भूलनी चाहिए कि कम-से-कम आधारभूत शिक्षा मिलना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसके बिना नागरिक के रूप में वह अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाएगा"। अप्रैल 2010 में "बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम" पारित करते समय माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने इस बात पर बल दिया था कि "... हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि लिंग और सामाजिक श्रेणी के भेद के बिना प्रत्येक बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। एक ऐसी शिक्षा जो उन्हें भारत का सक्रिय नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, मूल्य और मनोवृत्ति प्रदान करेगी"। श्रम शक्ति की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और आर्थिक ढांचा आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करेगा कि वृद्धि-प्रक्रिया अधिक रोजगार-उन्मुख हो।

11. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009 के अनुसार देश की कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने की वर्तमान क्षमता लगभग 3.1 मिलियन है। 2022 तक संचयी रूप से 500 मिलियन कवर करने का लक्ष्य है। नीति में इस बात को माना गया है कि देश का 93 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है किंतु जीडीपी में इसका योगदान 60 प्रतिशत ही है। इस क्षेत्र में कौशल वृद्धि होने से उत्पादकता, कार्य स्थिति और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी।

12. जब हम जीवन स्तर की बात करते हैं तब इसका सीधा संबंध आश्रय से होता है। आश्रय का अधिकार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा और रोजगार का अधिकार। अर्थव्यवस्था में सुधार होने और आय स्तर में काफी वृद्धि होने से पिछले दशक या उससे भी कुछ पहले से आवासों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। आवास वित्त बाजार में बैंक बड़े पैमाने पर आए हैं जिससे इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिला है। किंतु जब हम सभी के लिए आश्रय की बात करते हैं तब हमारा आशय आवास से होता है जो कि जनसामान्य की पहुंच में होना चाहिए। आवास की लागत को उस स्तर तक कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय और वित्तीय नवोन्मेष बहुत आवश्यक है।

13. रोजगार बाजार में प्रवेश करने वाले नए लोगों की संभावित भारी संख्या को लाभदायक रूप से काम में लगाने की दृष्टि से सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

14. किंतु यहां भारी चुनौतियां हैं। बिजली मुख्य चुनौती होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था के अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत और चीन की वैश्विक जीवाश्म ईंधन की मांग क्रमश: 16 प्रतिशत और 38 प्रतिशत होगी।

15. आने वाले समय में भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण होगी जिसके लिए युवाओं से नवोन्मेषी विचार, निजी क्षेत्र से समयोचित निवेश और सरकार से आवश्यक सहायता तथा पोषक नीतिगत वातावरण की आवश्यकता होगी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने 2010 में कानपुर में आईआईटी के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि, '... नवोन्मेष के दशक के रूप में घोषित अगले दस वर्ष भारत में फलदायी सिद्ध हो सकते हैं।

हमारे देश के अर्हताप्राप्त और प्रतिभासंपन्न लोगों को यहां की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे सामने की चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान ढूंढने होंगे'।

16. युवाओं और निजी कारोबारी उद्यमियों को खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। 1.2 बिलियन जनसंख्या वाले देश के लिए यह ठीक नहीं होगा कि वह अपनी ऊर्जा तथा आधारभूत खाद्य की आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहे। आप सब जानते ही हैं कि इन दो स्त्रोतों से प्रतिकूल आघातों से कई बार मुद्रास्फीति बढ़ जाती है जो कि उच्च वृद्धि की निरंतरता में बाधक बनती है। प्रोटीनयुक्त खाद्य मदों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृषि की अधिक उत्पादकता और पर्याप्त निवेश के लिए एक नई क्रांति की आवश्यकता है जिसमें नई प्रौद्योगिकी और अतिरिक्त निवेश प्रमुख होंगे। उच्च वृद्धि के साथ युवा जनसंख्या की औसत आय बढ़ने से दूध, मांस, अंडे, फल, साग और दलहन की मांग बढ़ेगी और आवश्यक आपूर्ति में वृद्धि किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना कठिन चुनौती होगी।

17. जब मैं उत्पादकता बढ़ाने की बात करता हूं तब मैं हमारी तुलना अमरीका या अन्य देशों से नहीं करता हूं। मेरा आशय अपने देश के विभिन्न भागों की उत्पादकता से होता है। हम मुद्रास्फीति बढ़ने का एक कारण लोगों द्वारा अधिक दूध पीना बतलाते हैं। यदि हम अधिक दूध का उत्पादन नहीं करेंगे तो दूध के दाम कैसे कम होंगे। आनंद का हमारा अनुभव देश के अन्य प्रांतों में क्यों नहीं दोहराया जा सकता। सीधी बात है कि दूध संबंधी मुद्रास्फीति कम रखने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हमें इस बात की आवश्यकता है कि उत्पादकता संबंधी चुनौती का सामना करने के लिए कम से कम हम अपने यहां की सफलताओं को तो अन्य स्थानों पर दोहराएं।

18. जब मैं नवोन्मेषी विचारों की बात करता हूं तब मुझे नकारात्मक नवोन्मेष के प्रति भी सचेत करना उचित होगा जिसने वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दिया और यह बात किसी के भी हित में नहीं है। वित्त और बैंकिंग का क्षेत्र युवाओं में सर्वोत्तम को आकर्षित करता है। कुछ चालाक, शिक्षित लोगों द्वारा वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग बिलियन से भी अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। मैं इस श्रोता समूह के सामने नैतिकता और मूल्ययुक्त प्रणाली के महत्त्व पर अलग से बल देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। भारत ने गंभीर वैश्विक संक्रमण के समय स्वयं को बचाये रखा। इस नैतिक जागरूकता को बढ़ाना हमारा सामूहिक दायित्व है। यहां द हिंदू जैसे विश्वसनीय समाचार पत्र अगुवाई कर सकते हैं।

19. हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार लोगों की हर आवश्यकता बैंक पूरी नहीं कर सकते। यह हर एक का दायित्व है कि वह अपने कल के भविष्य का निर्माण करे। इसमें नागरिक समाज शामिल है जैसे कि सेव निलगिरि कैंपेन जो कि निलगिरि में अच्छा कार्य कर रहा है। सरकार और बैंक अधिक से अधिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायता दे सकते हैं।

20. अब मैं पहले उल्लेख किये गये शिक्षा की गुणवत्ता और आवास के उदाहरण की ओर आता हूं। हाल के अनुमानों से पता चलता है कि जीडीपी में एक प्रतिशत वृद्धि होने से शिक्षा ऋण में 3 प्रतिशत और आवास ऋण में 5 प्रतिशत की वृद्धि होती है। जनसांख्यिकी के आधार पर, आय बढ़ने पर अधिकाधिक विद्यार्थी बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे। दूसरी ओर, हाल के वर्षों में निजी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लागत में काफी वृद्धि हुई है। शिक्षा के बाद अच्छा रोजगार मिलने पर अगला लक्ष्य अच्छे आवास का होता है। जहां बैंकों को युवाओं की अपेक्षा पूरी करने के लिए प्रतिस्पर्धी लागत पर ऋण तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, वहीं निजी क्षेत्र को यह समझना होगा कि इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुचित रूप से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित कृत्रिम रूप से निर्मित मुद्रास्फीति हमारी वृद्धि और विकास की महत्वकांक्षा को बाधित करेगी।

21. यह चर्चा मुझे हमारी भावी वृद्धि अर्थात समावेशी वृद्धि की महत्वपूर्ण चुनौती के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करती है। बढ़ती असमानता के साथ-साथ जारी यह उच्च वृद्धि आगे किसी न किसी समय रूक जाएगी। वित्तीय समावेशन के बिना समावेशी वृद्धि संभव न होने के कारण रिज़र्व बैंक का मानना है कि पहले तो देश में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक होनी चाहिए और यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि उचित और पारदर्शी उत्पादों/सेवाओं के साथ वित्त तक पहुंच सशक्तीकरण का एक स्त्रोत है जिससे लोग आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावी तरीके से सहभागी हो सकते हैं। अगली युवा पीढ़ी को उचित रूप से शिक्षित और नियोजनीय बनाये बिना और देश में असंख्य व्यष्टि उद्यमी तैयार किये बिना समावेशी वृद्धि का हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता।